Sugar

चीनी के उत्पादन के राज्यवार ढांचे से पता चलता है कि जहाँ 2003-04 में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त था, 2006-07 में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान ले लिया। 2006-07 में दो राज्यों महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश द्वारा कुल उत्पादन का 62 प्रतिशत उपलब्ध कराया गया। यदि इनमें कर्नाटक एवं तमिलनाडु जोड़ दिये जाए, तो ये चार राज्य अर्थात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु चीनी के उत्पादन का लगभग 81 प्रतिशत उपलब्ध कराते हैं।

एक और ध्यान देने योग्य बात है कि चीनी का उत्पादन जो 2003-04 में 135 लाख टन था बढ़कर 2006-07 में 288 लाख टन हो गया अर्थात इसमें तीन वर्षों के दौरान 109 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई।

सहकारी क्षेत्र का कार्यभाग :– हाल ही के वर्षों में चीनी उद्योग के सहकारी क्षेत्र के महत्व में वृद्धि हुई है। 1987-88 में सहकारी चीनी के 211 कारखाने थे जिनके द्वारा कुल चीनी के उत्पादन का 60 प्रतिशत उपलब्ध कराया गया था।

गन्ने का विकास :– गन्ने के उद्योग के विकास के लिए केन्द्रिय महत्व का कारण गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना था। प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन 1960-61 में 45 टन से बढ़कर 1970-71 में 48 टन और 2005-06 में बढ़कर 66 टन हो गया। उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाला दूसरा कारण गन्ने से सुक्रोस (Sucrose) की प्रतिशत प्राप्ति है। भारत में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन और इससे सुक्रोस की प्राप्ति दोनों ही कम थी।

गुड़ के उत्पादन से प्रतियोगिता :– भारत में 100 लाख टन से 10 टन चीनी प्राप्त की जाती थी परन्तु खांडसारी द्वारा 4 टन चीनी तैयार की जाती ~~थी~~ है। इस कारण गन्ने के खाड़सारी और गुड़ की ओर प्रयोग से देश को चीनी उत्पादन में नुकसान होता है। अतः गुड़ के कारखाने में गन्ने के प्रयोग से चीनी की कारखानो की तुलना में 35 से 40 प्रतिशत सुक्रोस प्राप्त किया जाता है। अतः यह अनिवार्य है कि चीनी, गुड़ और खांड़सारी के बीच कीमत प्रतियोगिता को दूर किया जाय। इन तीनो निकट स्थानापन्न वस्तुओं close substitutes

व. नेमा एक ही कीमत पर गन्नों की खोज की एकमुश्त नीति बनाई जाती। जब कि कारखानों को न्यायालय न राशी (जाने वाले गन्नों की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। गुड़ के इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाले गन्नों की कोई कीमत निर्धारित नहीं की जाती। इसका साफ परिणाम यह होता कि गुड़ का उत्पादन चीनी की कीमत पर बढ़ाया जाता है। इस नीति के होने के तौर पर गन्नों का निरन्तर चीनी कारखानों और गन्नों के उत्पादकों को उचित आधार पर नहीं हो पाता।

दोषपूर्ण सरकारी नीति:- चीनी सम्बन्धी नीतियों में हेरफेर (अनिश्चितता) को रखा जाता। गत वर्षों में भी नियंत्रण, विनियंत्रण और पुनः नियंत्रण की नीति लचीले रूप से लागू की गई। यद्यपि दुर्लभता के कारण से चीनी के पूर्ण विनियंत्रण के पक्ष में नहीं देना मुश्किल होगी। सरकार के लिए आंशिक नियंत्रण (partial control) की नीति का प्रयोग करना उचित होगा ताकि निर्धन वर्गों को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराई जा सके।

चीनी की ऊँची कीमतों की समस्या:- भारत में चीनी की उत्पादन-लागत अधिक होने के कारण इसकी कीमत विश्व-कीमत (World Price) की तुलना में ऊंची है। इसका कारण एक हद तक चीनी कारखानों द्वारा स्टॉक में हेरा-फेरी, जमाखोरी और चोर बाजारी के कारण भी थोक विक्रेता चीनी की कीमतें बढ़ा देते हैं। 1979-80 और 1980-81 के दौरान चीनी की कीमतें देश के विभिन्न भागों में 10-11 रु० प्रति किलोग्राम तक पहुंच गयी थी। परन्तु उत्पादन में तीव्र वृद्धि और चीनी की पर्याप्त उपलब्धि के कारण अब कीमत गिर गयी है।

उप-उत्पादकों की समस्या:- चीनी उद्योग की एक महत्वपूर्ण समस्या उप-उत्पादकों, विशेषकर शीरा और खोई (Bagasse) का पूर्ण उपयोग है। एक समय था जब खोई ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और कारखानों को यह पता नहीं था कि वे इकट्ठा हुए शीरे का क्या करें।